

बारे में

1. रिफाइनरियों का संक्षिप्त विवरण

1.1 गुवाहाटी रिफाइनरी (असम) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

गुवाहाटी रिफाइनरी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की पहली रिफाइनरी है, की स्थापना 17.29 करोड़ रुपए की लागत से रोमानिया के सहयोग से 1 जनवरी, 1962 को हुई थी, जिसकी डिजाइन क्षमता 0.75 एमएमटीपीए थी। रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता 1.00 एमएमटीपीए है। डीजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हाइड्रोजन जेनरेशन यूनिट सहित हाइड्रोट्रीटर यूनिट को वर्ष 2002 में स्थापित और चालू किया गया। वर्ष 2003 में रिफाइनरी ने इंडमैक्स यूनिट की भी स्थापना की। यह एक नवीन प्रौद्योगिकी है जिसे आईओसीएल आरएण्डडी केन्द्र द्वारा हेवी ऐंड्स को एलपीजी, मोटर स्पिरिट और डीजल ऑयल में उन्नत बनाने के लिए विकसित किया गया है। मोटर स्पिरिट गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत गुवाहाटी रिफाइनरी ने वर्तमान मोटर स्पिरिट गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिसंबर 2010 में नाफथा हाइड्रोट्रीटर, आइसोमेराइजेशन यूनिट और संबद्ध सुविधाओं की स्थापना की थी।

1.2 बरौनी रिफाइनरी (बिहार) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

पूर्वी भारत में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण 49.4 करोड़ रुपए की लागत से सोवियत यूनियन के सहयोग से किया गया था और इसे जुलाई, 1964 में चालू किया गया था। वर्ष 1969 तक इसकी क्षमता का 3.3 एमएमटीपीए तक विस्तार किया गया था और इसे वर्ष 2000 में 4.2 एमएमटीपीए तक आगे और बढ़ाया गया। अनलेडेड मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए 1997 में रिफाइनरी में एक कैटेलिटिक रिफार्मर यूनिट (सीआरयू) भी लगाई गई थी। बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन सहित वर्ष 2002 में रिफाइनिंग क्षमता को आगे और बढ़ाकर 6 एमएमटीपीए किया गया था जिसमें अपशिष्ट फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (आरएफसीसीयू) तथा हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट सहित डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट (डीएचडीटी) भी शामिल थी। एमएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना, जिसमें नाफथा हाइड्रोट्रीटर दूसरी हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट, आइसोमेराइजेशन, एफसीसी गैसोलीन डिसल्फ्युराइजेशन यूनिट आदि शामिल हैं जिन्हें वर्तमान मोटर स्पिरिट गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिसंबर 2010 में स्थापित किया गया था।

1.3 कोयाली रिफाइनरी (गुजरात) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

कोयाली रिफाइनरी का निर्माण सोवियत की सहायता से 26.00 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और उसे अक्टूबर, 1965 में चालू किया गया था। रिफाइनरी की प्रारंभिक क्षमता 2 एमएमटीपीए थी और इसे गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अंकलेश्वर, कलोल और नवागाम तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था। सितंबर 1967 में, रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर 3 एमएमपीटीए किया गया था। रिफाइनरी की क्षमता का गत्यावरोध दूर करने के उपायों के जरिए इसे 4.3 एमएमटीपीए तक आगे और बढ़ाया गया और अक्टूबर 1978 में 56.07 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना को कार्यान्वित करके इसे 7.3

एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया। अतिरिक्त प्रोसेसिंग सुविधाओं के कार्यान्वयन से रिफाइनरी 1989 में 9.5 एमएमटीपीए की क्षमता प्राप्त कर सकी थी। कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता के अनुसार द्वितीयक प्रोसेसिंग क्षमता की बराबरी करने के लिए हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट (एचसीयू) को दिसंबर, 1993 में चालू किया गया था। रिफाइनरी क्षमता का सितंबर 1999 में 3.0 एमएमटीपीए सीडीयू को चालू करके 12.5 एमएमटीपीए तक विस्तार किया गया था। डीजल गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा करने के लिए डीएचडीएस यूनिट की स्थापना की गई थी और इसे जून, 1999 में चालू किया गया था। इस रिफाइनरी की वर्तमान रिफाइनिंग क्षमता 13.70 एमएमटीपीए है। केरोसिन को उच्च मूल्य उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अगस्त, 2004 में एक लीनियर एल्काइल बेनजेन (एलएबी) संयंत्र चालू किया गया था। मोटर स्प्रीट गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीआरयू संयंत्र को अक्टूबर, 2006 में चालू किया गया था। अपशिष्ट उन्नयन परियोजना, जिसमें 2.1 एमएमटीपीए क्षमता का वीजीओ हाइड्रोट्रीटर, डीजल हाइड्रोट्रीटर, आइसोमेराइजेशन यूनिट तथा इंडियन ऑयल की 3.7 एमएमटीपीए क्षमता की सबसे बड़ी डिसेड क्रोकर यूनिट और संबद्ध इकाइयों के कार्यान्वयन से कोयाली रिफाइनरी अब भारी अपशिष्ट को ईंधन उत्पादों में उन्नत बनाने में सक्षम है और यह वर्तमान बीएस-III/बीएस-IV मोटर स्प्रीट तथा डीजल गुणवत्ता आवश्यकताओं के पूरी तरह अनुरूप है।

1.4 हल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

हल्दिया रिफाइनरी को जनवरी, 1975 में 2.5 एमएमटीपीए मध्य पूर्व कच्चे तेल की प्रोसेसिंग के लिए चालू किया गया था जिसके दो क्षेत्र हैं - एक ईंधन उत्पाद का और दूसरा ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक का उत्पादन करने के लिए। ईंधन क्षेत्र का निर्माण फ्रांस के सहयोग से तथा ल्यूब क्षेत्र का रोमानिया के सहयोग से किया था। ईंधन क्षेत्र में कैटेलिटिक सुधार यूनिट तथा केरो हाइड्रो-डिसल्फ्यूरेशन यूनिटें शामिल हैं जिन्हें जनवरी, 1975 में चालू किया गया था। रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता को मई 1988 में 3.16 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था और मई 1996 में गत्यावरोध दूर करने के उपायों के माध्यम से इसे आगे और 3.4 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। रिफाइनिंग क्षमता को मार्च 1997 में 1.0 एमएमटीपीए की नई कच्चे तेल की डिस्टिलेशन इकाई को चालू करके 4.4 एमएमटीपीए तक आगे और बढ़ाया गया था। कच्चे तेल की दूसरी डिस्टिलेशन इकाई की क्षमता को जून 1999 में 2.4 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था और जनवरी 2010 में इसे आगे और 4.1 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। रिफाइनिंग की वर्तमान रिफाइनिंग क्षमता 7.5 एमएमटीपीए है। हाइड्रोजन जेनरेशन यूनिट और डीजल हाइड्रो-डिसल्फ्यूरेशन (डीएचडीएस) यूनिट को क्रमशः अगस्त 1999 और सितंबर 1999 में डीजल गुणवत्ता को पूरा करने के लिए चालू किया गया था। कैटेलिटिक डि-वेक्सिंग यूनिट को मार्च, 2003 में चालू किया गया था जो एपीआई समूह-II ल्यूब बेस स्टॉक का उत्पादन कर सकता है और यह भारत में अपनी तरह की पहली यूनिट है। आंतरिक द्वितीयक प्रोसेसिंग इकाई के रूप में अपशिष्ट फ्लूराइज्ड कैटेलिटिक क्रैकर यूनिट (आरएफसीसीयू) को सितंबर 2001 में चालू किया गया था। मोटर स्प्रीट की गुणवत्ता आवश्यकता को पूरा करने के लिए एमएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना अक्टूबर, 2005 में चालू की गई थी। नई हाइड्रोजन जेनरेशन यूनिट को जनवरी '10 में चालू किया गया था तथा डिस्टिलेट उत्पाद में सुधार करने और बीएस-III/बीएस-IV के अनुरूप उच्च स्पीड डीजल (एचएसडी) का उत्पादन करने के लिए इसे फरवरी, 2010 में कार्यान्वित किया गया था।

1.5 मथुरा रिफाइनरी (उत्तर प्रदेश) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

6.00 एमएमटीपीए की क्षमता वाली मथुरा रिफाइनरी की स्थापना 253.92 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी। रिफाइनरी की स्थापना जनवरी, 1982 में की गई थी जिसमें फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू) तथा सल्फर रिकवरी इकाइयां (एसआरयू), जिन्हें जनवरी, 1983 में चालू किया गया था, शामिल नहीं थी। उपलब्ध कराई गई प्रमुख द्वितीयक प्रोसेसिंग इकाइयों में फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग इकाई (एफसीसीयू), विसब्रेकर इकाई (वीबीयू) तथा बिटुमन ब्लोइंग इकाई (बीबीयू) शामिल थीं। यद्यपि सीडीयू, वीडियू और बीबीयू इकाइयों को यूएसएसआर द्वारा डिजाइन किया गया था, एफसीसीयू और वीडियू की प्रौद्योगिकी को यूओपी, अमेरिका से प्राप्त किया गया था। अनलेडेड गैसोलीन के उत्पादन के लिए सतत कैटेलिटिक सुधार इकाई (सीसीआरयू) को 1998 में चालू किया गया था जिसकी प्रौद्योगिकी आईएफपी, फ्रांस ले ली गई थी। इस रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता की कठिनाइयों को दूर करने और पुनरुद्धार करने के लिए इसे 1989 में 7.5 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। 0.25% भार (अधिकतम) के न्यून सल्फर तत्व से एचएसडी के उत्पादन के लिए वर्ष 1999 में एक डीएचडीएस यूनिट चालू की गई थी। अतिरिक्त द्वितीयक प्रोसेसिंग इकाई के रूप में जुलाई 2000 में वन्स थू हाइड्रो क्रैकर (ओएचसीयू) परियोजना चालू की गई थी।

डीजल और मोटर स्पिट गुणवत्ता को पूरा करने के लिए डीजल हाइड्रो-ट्रीटर (डीएचडीपी) तथा पेनेक्स यूनिटों को क्रमशः मई, 2005 और जून, 2005 में चालू किया गया था। एफसीसीयू गैसोलीन के उपचार के लिए एमएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना को बीएस-III और बीएस-IV मोटर स्पिट की गुणवत्ता आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरवरी, 2010 में कार्यान्वित किया गया था। इस रिफाइनरी की वर्तमान रिफाइनिंग क्षमता 8.00 एमएमटीपीए है।

1.6 डिगबोई रिफाइनरी (असम) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

असम कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1901 में डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 14.10.1981 से रिफाइनरी का अधिग्रहण और विपणन प्रबंधन किया था तथा अलग से एक प्रभाग का सृजन किया। इस प्रभाग में रिफाइनरी और विपणन प्रचालन, दोनों शामिल थे। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापित क्षमता 0.50 एमएमटीपीए थी। रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता को जुलाई, 1996 में रिफाइनरी का आधुनिकीकरण करके 0.65 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। वर्ष 1999 में 1,70,000 टीपीए क्षमता की एक नई डिलेड कोकिंग यूनिट को चालू किया गया था। माइक्रो क्रिस्टालीन का उत्पादन अधिकतम करने के लिए एक नई घुलनशील डि-वैक्सिंग यूनिट की स्थापना की गई और उसे 2003 में चालू किया गया था। रिफाइनरी ने डीजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2003 में हाइड्रोट्रीटर और हाइड्रोजन संयंत्र की भी स्थापना की है। नाप्था हाइड्रोट्रीटर और आइसोमेराइजेशन यूनिटों को मोटर स्पिट गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत दिसंबर, 2010 में चालू किया गया था जिसका लक्ष्य वर्तमान मोटर स्पिट गुणवत्ता आवश्यकता को पूरा करना था।

1.7 पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

यह रिफाइनरी 1998 में बाहोली गांव, जिला पानीपत, हरियाणा में 3868 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई थी जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 6.0 एमएमटीपीए है। रिफाइनिंग क्षमता को अगस्त 2006 में 6 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए किया गया था। विस्तारित सुविधाओं में मुख्य द्वितीयक इकाइयों में हाइड्रो-क्रैकिंग यूनिट, डिसेल कोकिंग यूनिट, डीजल हाइड्रो-ट्रिटिंग यूनिट आदि शामिल हैं। देश के सबसे बड़े शुद्ध टेरपथालिक एसिड (पीटीए) संयंत्र को जून, 2006 में चालू किया गया था। बीएस-III और बीएस-IV मोटर स्प्रीट की गुणवत्ता आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनवरी, 2010 में एफसीसीयू गैसोलीन के उपचार के लिए एमएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना कार्यान्वित की गई थी। पानीपत रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता को नवंबर 2010 में इसके कच्चे तेल की डिस्टिलेशन इकाई के पुनरुद्धार के बाद 12.0 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 15.0 एमएमटीपीए किया गया था। वर्ष 2010 में डिसेल कोकिंग इकाई और वन्स थ्रू हाइड्रो-क्रैकिंग यूनिट की भी क्षमता वृद्धि की गई थी। इंडियन ऑयल का प्लास्टिक उद्योग, पानीपत नेफथा क्रैकर यूनिट, मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) यूनिट, पोली प्रोपीलीन (पीपी) यूनिट, लीनियर न्यून घनत्व पोली एथिलीन (एलएलडीपीई) और उच्च घनत्व पोली एथिलीन (एचडीपीई) यूनिटों को मार्च, 2010 से मई 2010 के बीच उत्तरोत्तर चालू किया गया था।

1.8 बोंगाईगांव रिफाइनरी (असम) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) को केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में 20 फरवरी, 1974 को निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य 1.0 एमएमटीपीए की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता वाली रिफाइनरी तथा एक पेट्रोसायन परिसर की स्थापना करना है जिसमें जाइलीन, डि-मिथाइल टेरपथालेट (डीएमटी) और पॉलियस्टर स्टैपल फाइबर (पीएसएफ) यूनिटें शामिल हैं। कंपनी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। परिसर का चरणों में निर्माण करके चालू किया गया था। कच्चे तेल की डिस्टिलेशन यूनिट-1, जिसे 1979 में चालू किया था, की क्षमता को अप्रैल, 1987 से गत्यावरोध दूर करके स्थापित किया गया था। कैटेलिटिक सुधार यूनिट की स्थापना 1984 में की गई थी। रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता को 1 एमएमटीपीए क्षमता की कच्चे तेल की डिस्टिलेशन इकाई की स्थापना करके जून, 1995 में 2.35 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। डिसेल कोकिंग यूनिट-II को 1996 में चालू किया गया था। कंपनी की अधिकृत पूंजी (इक्विटी) को दिसंबर, 1983 तक 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था और प्रदत्त पूंजी को 199.82 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार के पास 1990-91 तक पूंजी कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी धारित थी। सरकार ने बीआरपीएल में अपनी 25.54% की शेयरधारिता का यूटीआई तथा अन्य वित्तीय संस्थानों तथा 1991-92 से 1993-94 तक के दौरान कंपनी के कर्मचारियों में विनिवेश किया। दिनांक 29 मार्च 2001 को 74.46% का अंतिम विनिवेश इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में किया गया। परिणामस्वरूप, बीआरपीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। बोंगाईगांव रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को धारित कंपनी अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 25 मार्च 2009 से विलय कर दिया गया। डीजल और मोटर स्प्रीट गुणवत्ता को पूरा करने के लिए डीजल हाइड्रोट्रीटर तथा हलके नेफथा आइसोमेराइजेशन और हाइड्रोजन जेनरेशन यूनिट को 2011 में चालू किया गया है।

1.9 मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र) - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल):

मुंबई रिफाइनरी को सबसे पहले 1952 में स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया (स्टैनवैक) के रूप में निगमित किया गया था, जिसे 1.25 एमएमटीपीए की स्थापित क्षमता से 1954 में चालू किया गया था। वर्ष 1962 में स्टैनवैक का नाम एस्सो इंडिया लिमिटेड रखा गया। इसके साथ-साथ ल्यूब इंडिया लिमिटेड 165 एमएमटीपीए की क्षमता से ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक (एलओबीएस) का निर्माण करने के लिए अस्तित्व में आई थी। दिनांक 15 जुलाई, 1974 को एस्सो तथा ल्यूब इंडिया लिमिटेड के उपक्रमों को राष्ट्रीकृत किया गया था और उसका विलय करके हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) बनाई गई थी। वर्ष 1983 में, रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर 3.5 एमएमटीपीए किया गया था। वर्ष 1985 के दौरान, 2.0 एमएमटीपीए नए कच्चे तेल की डिस्टिलेशन इकाई को जोड़कर प्रमुख वृद्धि की गई थी जिससे रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 5.5 एमएमटीपीए हो गई। वर्ष 2009 में यूनिटों में वृद्धि करके आगे विस्तार किया गया और रिफाइनरी क्षमता बढ़ाकर 6.5 एमएमटीपीए हो गई। ल्यूब रिफाइनरी यूनिट का प्रथम विस्तार 1983 में हुआ था। इसकी क्षमता 225 एमएमटीपीए से बढ़कर 165 एमएमटीपीए हो गई थी। वर्ष 1995 में प्रोपेन डिवैक्सिंग यूनिट (पीडीयू) की क्षमता को आगे और बढ़ाया गया और एक प्रोपेन डी एस्फाल्टिंग यूनिट (पीडीए) जोड़ी गई थी। इस प्रकार क्षमता को बढ़ाकर 335 टीएमटीपीए एलओबीएस किया गया जो आज भी भारत में सबसे बड़ा है। वर्ष 2011 में रिफाइनरी ने ल्यूब तेल के मौजूदा ग्रेडों को उन्नत बनाने और बढ़ाने के प्रयास में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक (एलओबीएस) परियोजना की स्थापना की है। इस परियोजना से क्षमता बढ़कर 400 एमएमटीपीए हो जाएगी जिसमें एलओबीएस के वरिष्ठ गुणवत्ता समूह-II और III ग्रेड शामिल हैं। ऊर्जा की आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए रिफाइनरी ने वर्ष 1989 में 21 मेगावाट की क्षमता वाला एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीसीपी) स्थापित किया है जिसे बाद में 48 मेगावाट की विद्युत सृजन क्षमता तक पहुंचने के लिए 1995 और 2000 में चरणवार बढ़ाया गया था। वाहन ईंधन नीति के अनुसार मुंबई रिफाइनरी ने कई परियोजनाएं शुरू की थीं जैसे डीजल हाइड्रो डिसल्फ्यूरैजेशन (डीएचडीएस) परियोजना, जिसे यूरो-II/III गुणवत्ता के डीजल का उत्पादन करने के लिए 1.8 एमएमटीपीए की क्षमता से वर्ष 2000 में चालू किया गया था। इसके अलावा, ग्रीन ईंधन उत्सर्जन परियोजना (जीएफईसी) को यूरो-III और यूरो-IV गुणवत्ता के एमएस का उत्पादन करने के लिए वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। हाल में 2.2 एमएमटीपीए की क्षमता वाली परियोजना "डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचटी)" को बीएस-IV अनुरूप डीजल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चालू किया जा रहा है। वर्ष 2010 में 1.45 एमएमटीपीए की क्षमता वाली नई फ्लूराइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू-II) को चालू किया गया था। इसने एलपीजी और एमएस जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की है। इससे रिफाइनरी के मार्जिन में पर्याप्त वृद्धि होगी। रिफाइनरी विशेष उत्पादों जैसे फूड ग्रेड हेक्सेन, रबड़ प्रोसेसिंग (आरपीओ), डियाना प्रोसेसिंग ऑयल आदि का भी उत्पादन करती है, और इस प्रकार उत्पादों की व्यापक श्रृंखला कवर होती है। मुंबई रिफाइनरी फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र से 72% उच्च सल्फर कच्चे तेल की तथा मुंबई हाई से मुख्यतः 28% न्यून सल्फर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करती है। रिफाइनरी पर्यावरण को काफी महत्व देती है। इस संबंध में रिफाइनरी ने अत्याधुनिक एकीकृत बहिःस्राव उपचार संयंत्र (आईईटीपी) लगाया है, जो देश में अपनी तरह का पहला है। आईईटीपी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है और आगे कड़े मानकों को भी लागू करता है। इसे वर्ष 2010 में चालू किया गया था।

2.0 विशाख रिफाइनरी (आंध्र प्रदेश) - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल):

कैलटेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 1957 में एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी को चालू किया गया था जिसकी स्थापित क्षमता 0.675 एमएमटीपीए है। यह विशाखापट्टनम के पहले प्रमुख उद्योगों में से एक थी। भारत सरकार ने इस रिफाइनरी का 1976 में अधिग्रहण कर लिया था और परिणामस्वरूप इसका 1978 में एचपीसीएल में विलय हो गया था। पिछले वर्षों में रिफाइनिंग क्षमता को इकाइयों का गत्यावरोध दूर करके 1.5 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया था। वर्ष 1985 में 3.0 एमएमटीपीए कच्चे तेल की पृथक डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू-II), फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू-II), हाई समुद्र (अपतटीय टैंकर टर्मिनल) में कच्चा तेल प्राप्त करने की सुविधाएं तथा संबद्ध टैंक दूरी तथा उत्पाद प्रेषण सुविधाएं "विशाख रिफाइनरी विस्तार परियोजना" (वीआरईपी-I) के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस प्रकार स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 4.5 एमएमटीपीए किया गया था। दूसरा मुख्य विस्तार "विशाख रिफाइनरी विस्तार परियोजना-II" (वीआरईपी-II) वर्ष 1999 में हुआ था और रिफाइनिंग क्षमता को 4.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 7.5 एमएमटीपीए किया गया था। इसके उपरांत रिफाइनिंग क्षमता को 2009-10 में बढ़ाकर 8.3 एमएमटीपीए किया गया था। रिफाइनरी में दो एफसीसीयू थे जिनका गत्यावरोध समयावधि के दौरान दूर किया गया, जिससे द्वितीयक इकाई की क्षमता बढ़कर 2 एमएमटीपीए हो गई थी। इन क्षमता वृद्धि से द्वितीयक प्रोसेसिंग क्षमता विस्तारित कच्चे तेल की डिस्टिलेशन क्षमता के अनुरूप हो गई। रिफाइनरी में प्रोपीलेन रिकवरी यूनिट (पीआरयू) भी है जिसकी क्षमता 0.023 एमएमटीपीए है जो आसपास के उद्योगों की आवश्यकता पूरी करती है। वाहन ईंधन नीति के अनुरूप विशाख रिफाइनरी ने विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं जैसे 2.4 एमएमटीपीए की डीजल हाइड्रो डिसल्टफ्यूराइजेशन (डीएचडीएस) परियोजना, जिसे बीएस-III/II विशिष्टियों के अनुसार डीजल का उत्पादन करने के लिए वर्ष 2000 में चालू किया गया था। इसके अलावा, बीएस-II से बीएस-III और बीएस-IV में एमएस गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए स्वच्छ ईंधन परियोजना (सीएफपी) की वर्ष 2009 में स्थापना की गई थी। हाल में, "डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचटी)" परियोजना को बीएस-IV अनुरूप डीजल का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यह परियोजना पूरा होने के अंतिम चरण में है और इसके शीघ्र चालू होने की संभावना है। ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए रिफाइनरी ने वर्ष 1992 में 15 मेगावाट की क्षमता वाले कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) की स्थापना की थी। बाद में इसे प्रत्येक चरण में 40 मेगावाट तक बढ़ाया गया था तथा साथ ही वीआरईपी-II और वीआरसीएफपी परियोजनाओं की कुल सृजन क्षमता 94 मेगावाट बढ़ाई गई थी। विशाख रिफाइनरी फारस की खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त उच्च सल्फर कच्चे तेल के 60% का संसाधन करती है और रावा तथा आरआईएल केजी-डी6 जैसे घरेलू कच्चे तेल सहित पश्चिमी अफ्रीका और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों से प्राप्त न्यून सल्फर कच्चे तेल के 40% का आबंटन करती है। वर्ष 2010 में विशाख में सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा के चालू होने से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अब विशाख रिफाइनरी में अत्यधिक विशाल कच्चे तेल के वाहक (वीएलसीसी), जो 2 मिलियन बैरल तेल तक ले जाते हैं, आ

सकते हैं और, भविष्य में, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का इसके पास ही निर्माण होगा। वीएलसीसी से मितव्ययता और कच्चा तेल भाड़ा लागत में कमी आएगी।

2.1 मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र) - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल):

बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड के स्वामित्व में मुंबई में रिफाइनरी जनवरी 1955 में चालू हुई थी जिसकी मूल डिजाइन क्षमता 2.2 एमएमटीपीए कच्चे तेल की प्रोसेसिंग थी। बर्मा शेल का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 24 जनवरी 1976 को अस्तित्व में आई। इसके बाद से रिफाइनरी का कच्चे तेल का उत्पादन मौजूदा सुविधाओं का गत्यावरोध दूर करने से लगातार बढ़ा है और स्थापित क्षमता 1985 में बढ़कर 6 एमएमटीपीए हो गई। वर्ष 2005 में "रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना" (आरएमपी) के सफलतापूर्वक चालू होने से वर्तमान रिफाइनरी क्षमता 12 एमएमटीपीए हो गई है। मुंबई रिफाइनरी स्वदेशी कच्चे तेल की प्रोसेसिंग में अग्रणी है और वर्तमान में यह 72 प्रकार के कच्चे तेल की प्रोसेसिंग कर सकती है। क्षमता विस्तार के साथ रिफाइनरी ने पर्यावरण अनुकूल समूह-II बेस ऑयल के उत्पादन के लिए ल्यूब बेस ऑयल यूनिट चालू की है। रिफाइनरी ने क्षमता बढ़ाने और उन्नत ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए पुराने सीडीयू का विखंडन करके संबद्ध सुविधाओं सहित अत्याधुनिक डिस्टिलेशन यूनिट लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी एक आईएसओ 9001, 14001 और ओएचएसएस 18001 रिफाइनरी है। रिफाइनरी को गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त बोर्ड से गुणवत्ता प्रमाणपत्र की अद्वितीय विशेषता भी प्रदान की गई है।

2.2 कोच्चि रिफाइनरी (केरल) - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल):

कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की स्थापना भारत सरकार, फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी, अमेरिका तथा डेकन ब्रदर्स, कोलकाता के बीच 27 अप्रैल, 1963 को विनिर्माण करार के अनुसरण में 2.5 एमएमटीपीए की प्रारंभिक क्षमता के साथ की गई थी। सितंबर, 1973 में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 3.3 एमएमटीपीए और नवंबर 1994 में 4.5 एमएमटीपीए किया गया था। रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता को वर्ष 1994 में आगे और बढ़ाकर 7.5 एमएमटीपीए किया गया था और इसमें एक नई 3.0 एमएमटीपीए कच्चे तेल की डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू-2) शामिल की गई थी। इसके साथ-साथ एफसीसी यूनिट क्षमता को भी बढ़ाकर 1.4 एमएमटीपीए किया गया था ताकि कच्चे तेल की क्षमता की बराबरी की जा सके। क्षमता विस्तार के भाग के रूप में और ईंधनों के पर्यावरणीय विनियमों को पूरा करने के लिए बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी ने परियोजना सीईएमपी चरण-II को 2009-10 में कार्यान्वित किया है। परियोजना में सीडीयू-2 क्षमता को 3.0 से बढ़ाकर 5.0 एमएमटीपीए करना, नई सीसीआर यूनिट और नई वीजीओ एचडीएस यूनिट लगाना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप कोच्चि रिफाइनरी की क्षमता 9.5 एमएमटीपीए हो गई है। कोच्चि रिफाइनरी ने रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर 15.5 एमएमटीपीए करने और मूल्य वर्धन के लिए पेट्रोलियम विनिर्माण का विविधीकरण करने की एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना शुरू की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च, 2001 में केआरएल में भारत सरकार के शेयर अर्जित किए हैं। कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18 अगस्त, 2006 के

आदेश के अनुसरण में रिफाइनरी का भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विलय करके बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी बनाई गई है। व्यवसाय प्रबंधन प्रणाली (एसएपी) का कार्यान्वयन आधुनिक रिफाइनरी के लिए केआर के विकास के इतिहास में एक और मील का पत्थर था। कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के कार्यकलापों को जोड़ते हुए जुलाई, 2003 में एसएपी को कार्यान्वित किया गया था। रिफाइनरी ने प्रचालन और उद्यम संसाधन योजना के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कार्यान्वित की है। यह आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आईएसओ 9000:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रत्यायित रिफाइनरी है और इसने एनएबीएल (प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायित बोर्ड) द्वारा आईएसओ 17025 (गुणवत्ता नियंत्रण में परीक्षण पद्धति) प्रमाणन भी प्राप्त किया है। सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) और संबद्ध शोर टैंक की दिसंबर 2007 से प्रतिष्ठित कच्चे तेल की प्राप्ति सुविधाओं से रिफाइनरी अत्यधिक बड़े कच्चे तेल वाहक (वीएलसीसी) में कच्चा तेल प्राप्त करने में सक्षम हो गई है।

2.3 मनाली रिफाइनरी (तमिलनाडु) - चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल):

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), जो औपचारिक रूप से मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एमआरएल) के रूप में जाना जाता है, का गठन 1965 में एक संयुक्त उद्यम के रूप में भारत सरकार (जीओआई), अमोको और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) के बीच हुआ था जिनकी शेयरधारिता का अनुपात क्रमशः 74% : 13% : 13% था। बुनियादी स्तर पर सीपीसीएल रिफाइनरी की स्थापना 43 करोड़ रुपए की लागत से रिकार्ड 27 महीने में की गई थी जिसमें कोई अधिक समय या लागत नहीं आई। वर्ष 1985 में अमोको ने भारत सरकार के पक्ष में विनिवेश किया और भारत सरकार तथा एनआईओसी का शेयरधारिता प्रतिशत संशोधित करके क्रमशः 84.62% और 15.38% हो गया। बाद में भारत सरकार ने 19 मई, 1992 को 16.92% प्रदत्त पूंजी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्युचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों और बैंकों के पक्ष में विनिवेश किया, जिससे इसकी शेयरधारिता घटकर 67.7% रह गई थी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पुनर्गठन उपायों के भाग के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने वर्ष 2000-01 में भारत सरकार से इक्विटी प्राप्त की थी। मुंबई रिफाइनरी की क्षमता 10.5 एमएमटीपीए है और यह भारत में सबसे जटिल रिफाइनरियों में से एक है जिसमें ईंधन, ल्यूब और पेट्रोरसायन फीडस्टॉक उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं। सीपीसीएल ने तेल उद्योग में निम्नलिखित "अपनी तरह की पहली परियोजना" भी कार्यान्वित की है।

- 231 करोड़ रुपए की लागत से इसकी रिफाइनरी की जल आवश्यकता को बढ़ाने के लिए 5.8 एमजीडी समुद्री जल खारापन दूर करने की परियोजना।
- अपनी अक्षय ऊर्जा पहल के अंतर्गत 90 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2007 में पुशापाथुर, तमिलनाडु में 17.6 मेगावाट की क्षमता से एक पवन ऊर्जा फार्म चालू किया गया।

सीपीसीएल ने सितंबर, 2007 में पुशापाथुर, तमिलनाडु में 22 पवनचक्की वाला एक पवन चक्की फार्म चालू किया है जिसकी स्थापित क्षमता 17.6 मेगावाट है। इससे उत्पादित बिजली का

उपयोग कंपनी के कैप्टिव समुद्री जल डिसेलिनेशन संयंत्र में तमिलनाडु इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड (टीएनईबी) के साथ व्हीलिंग व्यवस्था के जरिए किया जा रहा है।

2.4 बासिन रिफाइनरी (नागापट्टिनम-तमिलनाडु) - चेन्नई पेट्रोलियम कावेरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल):

सीपीसीएल की दूसरी रिफाइनरी नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन में स्थित है। प्रारंभिक यूनिट की स्थापना वर्ष 1993 में 0.5 एमएमटीपीए की क्षमता से नागापट्टिनम में की गई थी और बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1.0 एमएमटीपीए किया गया था। कावेरी बेसिन रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल और उत्पादों को हैण्डलिंग करने के लिए नागापट्टिनम क्षेत्र में 2003 में एक ऑयल जेट्टी चालू की गई थी।

2.5 नुमालीगढ़ रिफाइनरी (असम) - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल):

नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो "असम समझौता रिफाइनरी" के नाम से लोकप्रिय है, की स्थापना असम के औद्योगिक और आर्थिक विकास पर बल देते हुए 15.8.1985 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक "असम समझौता" में भारत सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए गोलाघाट (असम) के जिले में नुमालीगढ़ में आधारभूत रिफाइनरी के रूप में की गई है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को 22.4.1993 को कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में वाणिज्यिक उत्पादन 1.10.2000 को शुरू हुआ था। एनआरएल का वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न है: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (61.65%); ऑयल इंडिया लिमिटेड (26%) और असम सरकार (12.35%)। इस रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता 3.0 एमएमटीपीए है। एनआरएल में 1.45 एमएमटीपीए की क्षमता वाला हाइड्रोक्रैकर तथा 0.306 एमएमटीपीए की क्षमता वाला डिसेल कोकर है। राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति के अनुसार हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बीएस-III/IV विशिष्टि को पूरा करने के लिए एनआरएल ने जून, 2010 में डीजल गुणवत्ता उन्नयन परियोजना (डीक्यूआईपी) को कार्यान्वित किया है। डीक्यूआईपी के कार्यान्वयन ने एनआरएल को रिफाइनरी के 100% क्षमता उपयोग पर एचएसडी के बीएस-III/IV ग्रेडों का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है।

2.6 मेंगलोर रिफाइनरी (कर्नाटक) - मेंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल):

मेंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोसायन लिमिटेड (एमआरपीएल) बेंगलुरु से लगभग 350 कि.मी. दूर हरे-भरे दक्षिण कन्नड़ जिला में पश्चिमी तट पर मेंगलोर में 15 एमएमटीपीए की क्षमता वाली एक बुनियादी रिफाइनरी का प्रचालन करती है। रिफाइनरी का 3.69 एमएमटीपीए का पहला चरण मार्च, 1996 में चालू हुआ था। दूसरे चरण में यह क्षमता बढ़ाकर 11.82 एमएमटीपीए की गई थी और तीसरे चरण में कंपनी ने इसकी क्षमता को 2012 में बढ़ाकर 15 एमएमटीपीए कर दिया है। एमपीआरएल की मूल रूप से भारत सरकार, एचपीसीएल और इंडियन रायन (आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज) के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसरण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा समर्थित एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी के रूप में स्थापना की गई थी। 28 मार्च, 2003 को ओएनजीसी ने ए.वी. बिरला ग्रुप की पूर्ण

शेयरधारिता प्राप्त कर ली थी और इसमें आगे 600 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी का निवेश किया जिससे एमआरपीएल ओएनजीसी की सबसे बड़ी सहायक कंपनी बन गई। उधारकर्ताओं ने ओएनजीसी द्वारा प्रस्तावित ऋण पुनर्गठन पैकेज (डीआरपी) को भी सहमति प्रदान की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 365 करोड़ रुपए के उनके ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल था। तत्पश्चात् ओएनजीसी ने डीआरपी के अनुसरण में उधारकर्ताओं को आबंटित इक्विटी प्राप्त की, जिससे एमआरपीएल में ओएनजी की शेयरधारिता बढ़कर 71.62 प्रतिशत हो गई। रिफाइनरी ने एक अनूठा डिजाइन प्राप्त किया है जिससे कच्चे तेल की प्रोसेसिंग को 24 से 46 एपीआई तक प्रोसेस किया जाता सकता है और इसमें स्वचालन की मात्रा उच्च कोटि की है। एमआरपीएल भारत में एकमात्र रिफाइनरी है जिसमें 2 हाइड्रोक्रैकर का उत्पादन करने वाला प्रीमियम डीजल (हाई सेटेन) है। यह भारत में एकमात्र रिफाइनरी है जिसमें हाई ओक्टेन के अनलेडेड पेट्रोल का उत्पादन करने के लिए 2 सीसीआर हैं। एमआरपीएल का शोधन उच्च मानक का है और पर्यावरण सुरक्षा समाज को की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एमआरपीएल ने स्थानीय वनस्पति के अनुरूप विशेष रूप से चयनित पौधों की प्रजातियों से पूरी रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में हरित पट्टी का भी विकास किया है।

2.7 ततिपका रिफाइनरी (आंध्र प्रदेश) - ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी):

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में ततिपका में सितंबर, 2001 में 27.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 0.066 एमएमटीपीए की क्षमता वाली ओएनजीसी की एक लघु रिफाइनरी (चरण-I) को चालू किया गया था। चरण-II के अंतर्गत 43.85 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 0.066 एमएमटीपीए की समान क्षमता वाली एक अतिरिक्त रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है।

2.8 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) (आरआईएल-डीटीए) (निजी क्षेत्र), जामनगर (गुजरात)

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की दो रिफाइनरियां हैं। पहली रिफाइनरी (आरआईएल-डीटीए) की वर्तमान क्षमता 33 एमएमटीपीए है। आरआईएल-डीटीए विश्व की सबसे बड़ी आधारभूत रिफाइनरी है जिसमें 1,550 केटीपीए पैराजाइलीन के उत्पादन के लिए एक पेट्रोसायन संयंत्र, 1000 केटीपीए पोली प्रोपीलीन के उत्पादन के लिए एक पॉलमर संयंत्र तथा गैस टर्बाइनों और वाष्प टर्बाइनों के जरिए 450 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता सहित एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र है।

2.9 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - एसईजेड (आरआईएल-एसईजेड) (निजी क्षेत्र) जामनगर (गुजरात)

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का आरआईएल में विलय होने के बाद, आरपीएल रिफाइनरी (जामनगर एसईजेड में एक इकाई) आरआईएल की दूसरी रिफाइनरी बन गई है। विलय योजना 11 सितंबर 2009 से प्रभावी है जिसकी अनुमोदित तारीख 1 अप्रैल 2008 है। दूसरी रिफाइनरी (आरआईएल-एसईजेड) की क्षमता 27 एमएमटीपीए है। एसईजेड रिफाइनरी का डिजाइन अद्वितीय है और इसका 'स्वच्छ ईंधन' प्रक्रिया संयंत्र तथा विन्यास अभिनव है। इसका डिजाइन अत्यधिक लचीलेपन के साथ उच्च स्तरीय है जिसके ग्रेडों को मितव्ययता के आधार पर बदला जा सकता है और मार्जिन को

बाजार के उतार-चढ़ाव के आधार पर दर्ज किया जा सकता है। नई एसईजेड रिफाइनरी भारत में पहली रिफाइनरी है जो गैसोलीन और डीजल के यूरो-IV ग्रेडों का उत्पादन कर सकती है।

2.10 एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल) (निजी क्षेत्र), वादीनगर (गुजरात)

निजी क्षेत्र की रिफाइनरी को वादीनगर, गुजरात में 10.50 एमएमटीपीए की स्थापित क्षमता से नवंबर 2006 में चालू किया गया था। बुनियादी रिफाइनरी का डिजाइन 10.5 एमएमटीपीए (210,000 बीपीएसडी) की प्रोसेसिंग करने के लिए बनाया गया था तथा इसमें द्वितीयक प्रोसेसिंग इकाइयां जैसे फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग, नेफ्था और डीजल हाइड्रोट्रीटर, सतत् कैटेलिटिक रिफार्मर, विस ब्रेकर, सल्फर रिकवरी और उत्पाद उपचार इकाइयां शामिल हैं। रिफाइनरी की क्षमता को अप्रैल '09 के दौरान पुनरुद्धार करके 14 एमएमटीपीए तथा 5 जून 2012 से 20 एमएमटीपीए किया गया था।

2.11 बीना रिफाइनरी - भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल) (मध्य प्रदेश)

भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल), जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और ओमान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओओसीएल), बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है, द्वारा 12,200 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 6 एमएमटीपीए की आधारभूत रिफाइनरी स्थापित की गई थी, जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा 20.05.2011 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस रिफाइनरी से मध्य और उत्तरी भारत में बीएस-III/IV अनुपालन ईंधनों सहित पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। रिफाइनरी के अलावा, परियोजना सुविधाओं में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रणाली सिंगल प्वाइंट मूरिंग सुविधा (एसपीएम), वादीनगर, गुजरात में कच्चे तेल का भण्डारण टर्मिनल (सीओटी) तथा वादीनगर से बीना तक (वीबीपीएल) कच्चे तेल की 935 कि.मी. लम्बी कंट्री क्रूड पाइपलाइन शामिल है।

2.12 गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी - एचपीसीएल - मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल), बठिण्डा (पंजाब)

गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी (जीजीएसआर), हिन्दुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) के स्वामित्व में है, जो एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस कंपनी के मालिक श्री एल.एन. मित्तल हैं। यह गांव फुलोखेड़ी, बठिण्डा, पंजाब, भारत में स्थित है। 9.0 एमएमटीपीए की क्षमता वाली इस रिफाइनरी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा 28 अप्रैल, 2012 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह रिफाइनरी तेल और गैस क्षेत्र में सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रमाण है। रिफाइनरी का निर्माण भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। बठिण्डा के कार्यनीतिक स्थल को देखते हुए रिफाइनरी भारत के उत्तरी राज्यों की ईंधन आवश्यकता को पूरा करेगी। एचएमईएल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (एचएमपीएल) को भी निगमित किया है, जो कच्चे तेल के क्रॉस कंट्री कच्चे तेल की प्राप्ति, भण्डारण और परिवहन के लिए एसपीएम का प्रचालन करेगा।
